



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2009/आषाढ़ 23, 1931

No. 239]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2009/ASADHA 23, 1931

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009

सं. 20/5/2009-खान-II.— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) की स्थापना कथिला सहित खनिज संसाधनों का पता लगाने के उद्देश्य से 1856 में नियमित सरकारी विभाग के तौर पर की गई थी। इसके प्रारंभ होने से लेकर एक सौ पचास वर्षों में जी एस आई ने विभिन्न भूविज्ञान कार्यकलापों में वृद्धि, विविधीकरण जारी रखा और भारतीय भूविज्ञान में इसका भूमिधर योगदान एक सुलिखित प्रमाण है।

2. स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्रीय आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के उद्देश्य से खनिज गवेषण तथा बेसलाइन सर्वेक्षणों में जी एस आई के कार्यकलाप कई गुना बढ़ गए हैं। 1960 के दशक के प्रारंभ से जी एस आई में तीव्रता से विस्तार हुआ और इसका पुनर्गठन हुआ तथा इसकी सक्षमताओं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए देश के अलग-अलग भागों में कई क्षेत्रीय तथा विशिष्ट स्कंधों की स्थापना की गई। खनिज गवेषण, इंजीनियरिंग तथा भूजल, भूविज्ञान, रासायनिक प्रयोगशाला कार्य, भूभौतिकीय सर्वेक्षण, ड्रिलिंग आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों को जो प्रारंभ में केंद्रीय मुख्यालयों से नियंत्रित होते थे क्षेत्रीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत किया गया। खनिज गवेषण तथा रासायनिक विश्लेषण/कार्यकलापों को बाद में प्रचालन मुख्यालयों के तौर पर पदनामित राज्य स्तर के कार्यालयों को वितरित किया गया। जबकि पूर्व में जी एस आई ने कलकत्ता, मद्रास, बम्बई स्थित तीन प्रचालनात्मक केंद्रों से लगभग एक सौ वर्षों तक प्रचालन किया आज देश के सभी कोनों में फैले 33 स्थानों पर इसके कार्यालय हैं।

3. वर्तमान में जी एस आई खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है लेकिन इसके तकनीकी स्वरूप के कार्य के कारण इसे पर्याप्त प्रचालनात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। जी एस आई के संगठनात्मक ढांचे को विशिष्टता तथा बहुविषयक अध्ययन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले ही पर्याप्त रूप से अनुकूल किया गया है। इसे बहुविषयक क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रचालन उप-इकाइयों के सृजन से संगठनात्मक रूप से तथा विशिष्ट विंगों के माध्यम से प्राप्त किया गया है जो विशिष्ट विषयों पर आवश्यकतानुसार आपस में विचार-विमर्श करते हैं। राज्य स्तर की प्रचालन इकाइयां फील्ड में कार्यक्रमों को निष्पादित करती हैं। बहुविषयक कार्यकलाप आमतौर से प्रचालन स्तर पर संसाधनों के पूलिंग द्वारा परियोजना पद्धति पर किए जाते हैं।

4. जी एस आई के सभी कार्यक्रम सरकारी नीतियों तथा अनुदेशों द्वारा संचालित होते हैं और संगत वर्तमान पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों के प्रावधानों का पालन किया जाता है। जी एस आई ने भूमि विज्ञान के क्षेत्र में कार्यक्रमों के प्रतिपादन और निर्दिष्ट करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है जिसमें कार्य की द्वािावृत्ति को रोकने और साहचर्य सुनिश्चित करने के लिए जी एस आई, स्टैक होल्डर मंत्रालयों तथा संगठनों और राज्य भूवैज्ञानिक विभागों के मध्य सूक्ष्म समन्वय स्थापित किया जाता है। केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड राज्यों के खनन तथा भूविज्ञान विभागों से इनपुट मुहैया कराते हैं जबकि केंद्रीय बोर्ड की उपसमितियां जी एस आई (विशिष्ट कार्यक्रमों सहित) से तथा स्टैक होल्डर मंत्रालयों तथा संगठनों से इनपुट मुहैया कराते हैं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समेकित कार्यक्रम केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड (सी जी पी बी) के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जो आगामी फील्ड सत्र के लिए राज्यवार तथा कार्यक्रमवार अंतिम कार्यक्रम तैयार करता है।
5. जी एस आई के कार्य में व्यावहारिक रूप से भूमि विज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र आते हैं जो इसके लिए परिकल्पित जिम्मेवारियों के व्यापक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। भूमि विज्ञान इसके स्वरूप से ही बहुत ही बहु विषयक है और मानव कार्यकलाप के पैमाने तथा विविधता यह अनिवार्य कर देती है कि प्रासंगिक बने रहने के उद्देश्य से जी एस आई को, इसके संगठनात्मक ढांचे और इसकी क्षमता-मानव तथा वैज्ञानिक, की चुनौतिपूर्ण आवश्यकताओं में, उपादान बनना है। इसको प्रासंगिक बने रहने के लिए जी एस आई किस डिग्री तक विशिष्ट बनता है तथा बहु-विषयक ज्ञान का विकास कर सकता है यह महत्वपूर्ण है।
6. देश में भूविज्ञान की मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने में जी एस आई को समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार ने 7 जनवरी, 2008 के संकल्प के तहत जी एस आई के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) का गठन किया। एच पी सी ने 13 बैठकों में चर्चाएं की और सरकार को 31 मार्च, 2009 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यकलाप पर रिपोर्ट नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने जी एस आई को एक विश्व स्तर का भूवैज्ञानिक संस्था बनाने की परिकल्पना की है और सिफारिशें की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिशा, चार्टर, कार्य, लक्ष्य, नीतियां और माइलस्टोन निश्चित किए हैं।
7. एच पी सी ने तदनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ढांचे को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है। इस प्रस्तावित ढांचे में 5 समर्पित मिशन तथा 3 सपोर्ट प्रणालियां होंगी। विगों के नीति संबंधी कार्य मिशनों में विलय हो जाएंगे और निष्पादन संबंधी कार्य क्षेत्रों में विलय हो जाएंगे। इससे निर्णय लेने के सभी स्तरों का बेहतर सरलीकरण तथा समन्वय के माध्यम से सहज कार्यकरण सुविधाजनक हो जाएगा। नई प्रणाली में मिशन कार्यकलापों की आयोजना, क्षेत्रों (तथा राज्य इकाइयों) को लक्ष्य देने, समन्वयन, संसाधनों की वृद्धि, कार्य निष्पादन की मानीटरिंग तथा क्षेत्रीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी रिपोर्टें देने के लिए जिम्मेवार होंगे तथा सपोर्ट प्रणालियां आंतरिक प्रबंध निष्पादन तथा रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण के लिए जिम्मेवार होंगी। क्षेत्र मिनी जी एस आई जैसे हो जाएंगे और कार्यात्मक रूप अर्द्ध-स्वायत्ती होंगे यदि उनके वर्ष के कार्यक्रम (सी जी पी बी) में पास हो जाते हैं और निधियां मुहैया कराई जाती हो। इस प्रकार मिशनों तथा क्षेत्रों को अधिकाधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय तथा प्रशासनिक सपोर्ट को सुदृढ़ किया जाएगा। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
8. जी एस आई को शक्तिशाली बनाने की समग्र प्रक्रिया के सहायक के तौर पर एच पी सी की प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश जी एस आई को सम्बद्ध कार्यालय का रूतबा प्रदान करने से संबंधित है। बृहत्तर कार्यात्मक स्वायत्तता की आवश्यकता तथा जी एस आई के कार्य के स्वरूप द्वारा जनित आकांक्षाओं के कारण तथा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक आकाश में इसके स्थान के आधार पर इस संबंध में जी एस आई के भीतर लम्बे समय से मांग की जाती रही है। जी एस आई के मौजूदा ढांचे का विश्लेषण करने ने बाद एच पी सी का मत व्यक्त किया कि लक्ष्यों तथा प्रौद्योगिकियों को देखते हुए तथा मौजूदा ढांचे की प्रक्रिया की सीमाओं के कारण भी जी एस आई के ढांचे में परिवर्तन करने की जरूरत है। एच पी सी ने यह भी पाया कि विगत

में जी एस आई के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बावजूद, कुछ विशिष्ट सिफारिशों को प्रभावी नहीं बनाए जाने के कारण, अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। एच पी सी ने प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जो प्रशासनिक मंत्रालय के संबंध में जी एस आई का स्थान तथा पर्याप्त दीर्घकालिक नीतिगत आयोजना और कार्यात्मक स्वायत्ता निश्चित करेंगे।

9. उचित विचार-विमर्श के पश्चात् समिति की यह राय थी कि एक निष्पक्ष वैज्ञानिक संस्थान के रूप में जीएसआई की प्रतिष्ठा और सुविज्ञता प्रमाणित है। इसकी भावी दिशा भी इस अनुबोधन की पुष्टि करती है। तदनुसार एचपीसी ने सिफारिश की कि जीएसआई को अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्गीकृत करने के बजाए इसे तत्काल 'सम्बद्ध कार्यालय' बना दिया जाना चाहिए क्योंकि शासकीय शब्दावली में एक अधीनस्थ कार्यालय सरकार की नीतियों के व्यापक कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है और सुविज्ञता के अपने क्षेत्र में तकनीकी मामलों के निपटान में विभाग की सहायता करता है। इसकी तुलना में 'सम्बद्ध कार्यालय' अपने सम्बद्ध विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी निदेश देने के लिए सामान्यतया उत्तरदायी है। यह तकनीकी सूचना के भण्डार के रूप में भी कार्य करता है और इसके द्वारा विचारित प्रश्नों के तकनीकी पहलुओं पर विभाग को सलाह देता है। एचपीसी की यह राय थी कि अपने दीर्घकालीन और प्रतिष्ठित इतिहास और भूविज्ञान के क्षेत्र में इसकी श्रेष्ठता के साथ जीएसआई को वास्तव में अधीनस्थ अथवा सम्बद्ध कार्यालय के रूप में वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और वास्तव में इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। बहरहाल, इसे अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्गीकृत करना निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है। तदनुसार, समिति ने सिफारिश की कि प्रशासनिक अपेक्षाओं के मद्देनजर, जीएसआई को तत्काल 'सम्बद्ध कार्यालय' के रूप में वर्गीकृत किया जाए चाहे यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हो कि इसे 'अधीनस्थ कार्यालय' के रूप में वर्गीकृत न किया जाए।

10. मंत्रालय ने एचपीसी की सिफारिशों पर विचार किया और जीएसआई द्वारा सम्बद्ध कार्यालय की मांग करते हुए भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर सरकार ने जीएसआई को सम्बद्ध कार्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु अपना अनुमोदन दे दिया है। तदनुसार, यह घोषित किया जाता है कि इस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और इसका मुख्यालय, पूर्व की भांति, कोलकाता में रहेगा। जीएसआई के नीति निष्पादक और समन्वयन कार्यालयों तथा फील्ड कार्यालयों की सूची संलग्न अनुबंध के अनुसार होगी।

11. उपर्युक्त के फलस्वरूप, यह निदेश दिया जाता है कि :

(i) दिल्ली में डीजी कैम्प कार्यालय (उपयुक्त पुनर्गठन के माध्यम से सम्पर्क कार्यालय से संवर्धित) जीएसआई और मंत्रालय के बीच विचार-विनिमय का मुख्य बिन्दु होगा। वरिष्ठ उप महानिदेशक अथवा उप महानिदेशक को इस कार्यालय के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) सभी तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों में जीएसआई और मंत्रालय के बीच कोई पत्राचार नहीं होगा। इसके बजाय, जीएसआई द्वारा मंत्रालय को फाइल दिल्ली के डीजी कैम्प कार्यालय (डीजीसीओडी) के माध्यम से भेजी जाएगी जो अपर/संयुक्त सचिव (खान मंत्रालय) को चिह्नित (मार्कड) होगी और वे उसी फाइल पर सभी अनुमोदन/निदेश प्राप्त करेंगे और सूचित करेंगे।

(iii) योजना, बजट, व्यय, क्रेडिट/कोर्ट मामलों, भर्ती नियमों, नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि सहित सभी वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के संबंध में मामलों पर पूर्व की भांति, पत्राचार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में जीएसआई का कार्मिक प्रभाग नीतिगत मामलों जिनके लिए मंत्रालय का प्रशासनिक अनुमोदन लेना अपेक्षित है, को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आदि के साथ सीधे ही पत्राचार करने हेतु प्राधिकृत है।

12. उपर्युक्त व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से लागू हैं। मंत्रालय महानिदेशक, जीएसआई के परामर्श से इन व्यवस्थाओं को समय-समय पर संशोधित कर सकता है।

एस. विजय कुमार, अपर सचिव

अनुबंध

संबद्ध कार्यालय के तहत जीएसआई की इकाइयों का विवरण

क) नीति कार्यान्वयन और समन्वयकारी कार्यालय

1. महानिदेशक का कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता (समर्थन प्रणालियों सहित)
2. पांच मिशन, नामतः
 - बेसलाइन भू-विज्ञान मिशन (कोलकाता में अवस्थित)
 - प्राकृतिक संसाधन आंकलन मिशन (नागपुर में अवस्थित)
 - भू-सूचना मिशन (कोलकाता में अवस्थित)
 - आधारभूत और बहु विषयक भू-विज्ञान मिशन (कोलकाता में अवस्थित)
 - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण मिशन (हैदराबाद में अवस्थित)
3. दिल्ली में महानिदेशक का कैंप कार्यालय। इस कार्यक्रम में सीजीपीबी सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विज्ञान नीति एवं समन्वय, वाणिज्यिक प्रचालन और भू-विज्ञान भागीदारियां शामिल होंगे।
4. उप-महानिदेशक (पी) का कार्यालय, जीएसआई का नोडल कार्यालय, खान मंत्रालय, नई दिल्ली में अवस्थित। इस कार्यालय के अधीन कार्मिक विभाग और विधिक कक्ष शामिल होंगे।

ख) फील्ड कार्यालय

1. क्षेत्रीय परिचालन कार्यालय, नामतः
 - पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (कोलकाता में अवस्थित)
 - पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय (जयपुर में अवस्थित)
 - उत्तरी क्षेत्र कार्यालय (लखनऊ में अवस्थित)
 - दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय (हैदराबाद में अवस्थित)
 - मध्य क्षेत्र कार्यालय (नागपुर में अवस्थित)
 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (शिलांग में अवस्थित)
2. देश के विभिन्न भागों में अवस्थित राज्य इकाई कार्यालय।
3. देश के विभिन्न भागों में अवस्थित, आवश्यकता के आधार पर कैंप कार्यालय (ये सर्वेक्षण, गवेषण और परियोजना आधार के प्रयोजनों के लिए अस्थाई कार्यालय होंगे)।

व्याख्या : फील्ड प्रशिक्षण केंद्र और ड्रिल कोर भंडार क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय कार्यालय के भाग होंगे।

MINISTRY OF MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 7th July, 2009

No. 20/5/2009-M-IL.—The Geological Survey of India (GSI) was established as a regular Government Department in 1856 with the objective of locating mineral resources including coal. In the hundred and fifty years since its inception, GSI has continued to grow, and diversify into various geoscience activities, and its yeoman contribution to the Indian Geoscience is well documented.

2. After independence, GSI's activities in mineral exploration as well as baseline surveys have increased manifold in order to sustain the momentum of national economic development. GSI expanded rapidly since the early 1960s and was restructured and a number of Regions and specialized Wings were set up in different parts of the country to meet the increasing demands on its capabilities. Specialized activities like mineral exploration, engineering and groundwater geology, chemical laboratory work, geophysical survey, drilling etc. which were initially controlled from the Central Headquarters were decentralized to the Regional level. Mineral exploration as well as chemical analysis/ activities were later distributed even to State level offices designated as 'Operational Headquarters'. While GSI earlier operated from three operational centers at Calcutta, Madras and Bombay for nearly a hundred years, today it has offices at thirty-three locations spread in all the corners of the country.

3. The GSI is currently a subordinate office of the Ministry of Mines, but has considerable operational autonomy due to the scientific nature of its work. The organizational structure of GSI is already substantially oriented to meet the needs of specialization as well as multidisciplinary study. This has been achieved organizationally by creating multi-disciplinary Regional Offices with operational sub-units, and through separate specialized 'Wings' which interact with the Regional Offices on specialized

25794809-2

subject matters to the extent necessary. Operational units at State level execute the programmes in the field. Multi-disciplinary activities are generally taken up in a 'project' mode by pooling resources at the operational level.

4. All the programmes of GSI are guided by the Government policies and directives and follow the provisions of relevant current Five-Year Plan document. The GSI has evolved a mechanism for formulation and detailing of the programmes in the earth science area, through close co-ordination between GSI, stakeholder Ministries and Organizations and State Geological Departments to avoid duplication of work and ensure synergy. The principal mechanism for this is the Central Geological Programming Board. State Level Programming Boards provide inputs from the State Departments of Mining and Geology while subcommittees of the Central Board provide the inputs from within GSI (including special programmes) as well as from stakeholder Ministries and Organizations. The consolidated programme, prioritized on the basis of resources available, is brought before the Central Geological Programming Board (CGPB) which sets out the final programme for the ensuing field season, State-wise and activity wise.

5. GSI's work encompasses practically the entire gamut of earth science activities reflecting the broad nature of responsibilities envisaged for it. Earth science by its very nature is highly multi- disciplinary and the scale and diversity of human activity makes it essential that GSI, in order to remain relevant, has to factor in very challenging requirements into its organizational structure and its capacity – human as well as scientific. The degree to which GSI is able at once to specialize as well as to develop multi-disciplinary knowledge is crucial for it to remain relevant.

6. To enable GSI to meet the present day requirements of Geoscience in the country, the Government set up a High Powered Committee (HPC) for the GSI vide Resolution dated 7th January 2008. The HPC held 13 rounds of discussions and presented its report titled "Report on the functioning of the Geological Survey of India" to the Government on 31st March 2009. The Committee visualized making the GSI a world-class

Geoscientific Institution and gave recommendations, which inter-alia set out the Vision, Charter, functions, goals, strategies and milestones.

7. The HPC has accordingly suggested reorganization of the structure of the Geological Survey of India. In this proposed structure, there will be 5 dedicated Missions and 3 Support Systems. The policy function of the Wings would be merged into the Missions and the execution part into the Regions. This will facilitate smooth functioning through better streamlining and coordination of decision making at all levels. In the new system the Missions will be responsible for planning activities, giving targets to the Regions (and State units), coordinating, augmenting of resources, monitoring performance and giving sectoral scientific and technical reports and the Support systems will be responsible for the internal management execution and reporting and analysis. Regions will become like mini GSIs and will be functionally semi-autonomously once their programme for the year is cleared (in CGPB) and funds provided. Thus more and more administrative and financial powers will be delegated to the Missions and Regions, and financial and administrative support at Regional level will be strengthened for the purpose. The implementation of these recommendations are underway.

8. As an adjunct to this entire process of empowering GSI, one of the major recommendations of the HPC pertains to the grant of Attached Office status to the GSI. There has been a long standing demand within GSI in this regard based both on the basis of the need for greater functional autonomy and because of aspirations created by the nature of GSI's work and its place in the national geoscientific firmament. After an analysis of the present structure of the GSI, the HPC held that there is a need to change the structure of GSI in keeping with goals and technologies and also in response to the limitations of the existing structure. The HPC further observed that despite the recommendations of the various Committees set up to improve the performance of GSI in the past, the expected improvements have not taken place due to the fact that some of the specific recommendations were not given effect. The HPC deliberated on the key issues that would determine the GSI's place in relation to the administrative Ministry and to ensure adequate long-term policy planning and functional autonomy.

25794700-3

9. The Committee after due consideration, was of the view that GSI had an established reputation and expertise as an impartial scientific institution. The Vision too reaffirmed this perception. The HPC accordingly recommended that GSI should immediately be made an 'Attached Office' rather than be classified as a Subordinate Office, since in official parlance, a Subordinate Office is responsible for detailed execution of the policies of the Government, and assists the Department in handling technical matters in its respective field of specialization. An 'Attached Office' by contrast is generally responsible for providing executive direction for implementation of the policies laid down by the department to which it is attached. It also serves as a repository of technical information and advises the Department on technical aspects of questions dealt by it. The HPC was of the view that with its long and distinguished history and its preeminence in the field of geoscience, GSI actually needed no classification as a subordinate or Attached Office and should actually be classified as an Institution of National Importance. In any case, it was certainly not appropriate to classify it as a subordinate office. The Committee accordingly recommended that GSI may be immediately classified in view of administrative requirements, as an 'Attached Office' if only to ensure it is not classified as a 'Subordinate Office'.

10. The recommendations of the HPC were considered by the Ministry and based on the proposal sent by the GSI seeking Attached Office status, the Government has approved the grant of Attached Office status to the GSI. Accordingly, with effect from the date of publication of this order, it is declared that the Geological Survey of India shall be an Attached Office in the Ministry of Mines, Government of India with its headquarters in Kolkata as heretofore. The list of policy executing and coordinating offices and Field Offices of GSI will be as per Annexure attached.

11. Consequent to the above, it is directed that:-

- (i) The DG Camp Office in Delhi (upgraded from the Liaison Office through suitable reorganization) will be the main point of interface between GSI and the Ministry.

A Senior Deputy Director General or Deputy Director General shall be designated as Head of Department for the office.

- (ii) In all technical and scientific matters, there will be no correspondence between GSI and the Ministry. Instead, the file will be sent by the GSI to the Ministry through the DG Camp Office in Delhi (DGCOD) marked to the Additional/Joint Secretary (Ministry of Mines), who will obtain and convey all approvals/directions on the same file.
- (iii) In respect of all financial and administrative matters, including Plan, Budget, Expenditure, CAT/Court Cases, Recruitment Rules, appointments, promotions etc., cases will be processed as heretofore, by correspondence. Personnel Division of GSI in Delhi is authorized to correspond directly with Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Department of Personnel and Training etc. on all matters excepting those relating to matters of policy etc. requiring administrative approval of the Ministry.

12. These arrangements come into force with immediate effect. The Ministry may modify the arrangements from time to time in consultation with DG, GSI.

S. VIJAY KUMAR, Addl. Secy.

ANNEXURE

DETAILS OF GSI's UNITS UNDER THE ATTACHED OFFICE

A. Policy Executing and Coordinating Offices

1. Office of the Director General, Geological Survey of India, Kolkata (including support systems).
2. Five Missions, namely:-
 - Baseline Geosciences Mission (located at Kolkata).
 - Natural Resource Assessment Mission (located at Nagpur).
 - Geoinformatics Mission (located at Kolkata).
 - Fundamental and Multi disciplinary geosciences Mission (located at Kolkata).
 - Training and capacity building Mission (at Hyderabad).

3. DG's Camp Office in Delhi. This Office shall include CGPB Sectt., International Cooperation, Science Policy & Coordination, Commercial Operation and Geoscience Partnerships.
4. Office of the Deputy Director General (P), Nodal Office of GSI, Ministry of Mines, located at New Delhi. This office shall have under it, the Personnel Division and Legal Cell.

B. Field Offices

1. Regional Operational Offices, namely:-
 - Eastern Region Office (located at Kolkata).
 - Western Region Office (located at Jaipur).
 - Northern Region Office (located at Lucknow).
 - Southern Region Office (located at Hyderabad).
 - Central Region Office (located at Nagpur).
 - North Eastern Region Office (located at Shillong).
2. State unit Offices located at various parts of the country.
3. Camp Offices on need basis, located at various parts of the country. (These shall be the temporary offices for the purposes of survey, exploration and project based).

Explanation:- Field Training Centres and Drill Core Repositories will be part of the Regional Office having jurisdiction.